बकाया पोर्टफोलियो के अनुसार दी गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति के अनुसार	कुल बकाया ऋण और निवेश
31.03.1994	3755.30
31.03.1995	3931.20
31.03.1996	4425.31

तथापि बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत संघटकों के बारे में सूचना प्रगट नहीं की जा सकती है।

(ग) जी नहीं। आई डी बी आई ने सूचित किया है कि सावधि ऋण का संवितरण सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा ऋण स्वीकृति से संबंधित विभिन्न पूर्व संवितरण की विशेष शर्तों तथा अन्य शर्तों के अनुसार प्रवर्तक के अनुरूपीय अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) आई डी बी आई सामान्य शर्तें निर्धारित करता है, जो सभी मामलों में समान रूप से लागू होती हैं। अलग-अलग मामलों के आधार जहां यह महसूस किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और चलाने अर्थात प्रबंधन को सुदृढ़ करने, मशीनरी सप्लायरों, सहयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादन गारंटी, आदि के लिए विशेष ध्यान देने / शर्तें रखने की आवश्यकता है, वहां पर विशेष शर्तें निर्धारित की जाती है।

प्रश्न के भाग (क) से (घ) के संबंध में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू टी आई) से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुमत जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Evasion of Income Tax by Reliance Industries

881. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income Tax Department has discovered that Reliance Industries has evaded income tax to the tune of Rs. 80 crore;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to set up a committee with representatives of the Central Bureau of Investigation, Revenue Intelligence, Securities and Exchange Board of India and Income Tax authorities to further investigate the case as the case involves share transactions?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Income Tax Department has raised a demand aggregating to Rs. 76.25 crores on the 23 satellite companies of Reliance Industries Ltd. relating to the Assessment Year 1993-94.

(c) At present there is no proposal to set up a committee with representatives of CBI, Revenue Intelligence, SEBI & Income Tax authorities.

यात्री विमान सेवाओं में सुधार

882. श्री एस.एस. सुरजेवालाः
श्री अजीत जोगीः

क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान यात्री विमान सेवाओं में सुधार, विमान-बेड़े के बेहतर उपयोग, विमानों के रख-रखाव और विमान सेवा-प्रचालन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है; और